

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 980

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है)

घरेलू बचत और देनदारियाँ

980. सुश्री सयानी घोष:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले दस वर्षों के दौरान देश में प्रति व्यक्ति घरेलू ऋण का वर्षवार ब्यौरा क्या है;
- (ख) पिछले दस वर्षों के दौरान, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घरेलू बचत का वर्षवार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह सच है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान घरेलू देनदारियों में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो पिछले दस वर्षों के दौरान घरेलू देनदारियों का जीडीपी के प्रतिशत के रूप में ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार 'मध्यम वर्ग' को उपभोक्ताओं की एक श्रेणी के रूप में मान्यता देती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार ने यह ध्यान दिया है कि मध्यम वर्ग सबसे अधिक प्रभावित उपभोक्ता है, जिसके कारण 'सिकुड़ते मध्यम वर्ग' की स्थिति पैदा हो रही है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, घरेलू वित्तीय देनदारियों के स्टॉक संबंधी डेटा मार्च 2019 से उपलब्ध है। तदनुसार, मार्च 2019 से मार्च 2024 तक प्रति व्यक्ति घरेलू वित्तीय देनदारियों से संबंधित डेटा अनुलग्नक-क में प्रस्तुत किया गया है।

(ख) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार, घरेलू बचत संबंधी नवीनतम उपलब्ध डेटा वर्ष 2022-23 के लिए है। तदनुसार, 2014-15 से 2022-23 तक सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में घरेलू बचत का ब्यौरा अनुलग्नक-ख में दिया गया है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, घरेलू वित्तीय देनदारियों के स्टॉक से संबंधित डेटा मार्च 2019 से उपलब्ध है। तदनुसार, मार्च 2019 से मार्च 2024 तक जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घरेलू वित्तीय देनदारियों से संबंधित डेटा अनुलग्नक-ग में प्रस्तुत किया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार ने मध्यम वर्ग की व्यय क्षमता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में महत्वपूर्ण उपायों का प्रस्ताव किया है। एक प्रमुख सुधार उपाय के तहत, केंद्रीय बजट ने प्रस्ताव किया है कि नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। बजट में करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए व्यक्तिगत आयकर के स्लैब और दरों में बदलाव का भी प्रस्ताव किया गया है। उम्मीद है कि नए ढांचे से मध्यम वर्ग के करों में काफी कमी आएगी और उनके हाथ में अधिक पैसा बचेगा, जिससे घरेलू खपत, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार के अन्य उपायों में बढ़ी हुई पेंशन योजनाएँ, किफायती आवास के लिए सहायता, जन स्वास्थ्य योजनाएँ, उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता और टिकाऊ अवसंरचना को बढ़ावा देने की पहलें शामिल हैं। सरकार के पास 'सिकुड़ते मध्यम वर्ग' सिंड्रोम के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

अनुलग्नक-क

मार्च के अंत तक	प्रति व्यक्ति घरेलू वित्तीय देनदारियाँ (₹ में)
2019	46,898
2020	52,090
2021	57,306
2022	63,000
2023	73,887
2024	86,713

स्रोत: घरेलू वित्तीय देनदारियों के स्टॉक के आंकड़े आरबीआई से लिए गए हैं। प्रति व्यक्ति घरेलू वित्तीय देनदारियों की गणना के लिए जनसंख्या अनुमान राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी, एमओएसपीआई से लिए गए हैं।

अनुलग्नक-ख

वर्ष	घरेलू बचत (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)
2013-14	20.3
2014-15	19.6
2015-16	18.0
2016-17	18.1
2017-18	19.3
2018-19	20.3
2019-20	19.1
2020-21	22.7
2021-22	20.1
2022-23	18.4

अनुलग्नक-ग

मार्च के अंत तक	घरेलू वित्तीय देनदारियाँ (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)
2019	32.9
2020	34.7
2021	39.1
2022	36.5
2023	37.9
2024	41.0
